भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3753

12.08.2025 को उत्तर के लिए नियत

पीएम ई-ड्राइव योजना के अंतर्गत सार्वजनिक परिवहन

3753. **श्री कृपानाथ मल्लाह:**

श्री कामाख्या प्रसाद तासाः

डॉ. विनोद कुमार बिंदः

श्री प्रताप चन्द्र षडंगी:

श्रीमती बिजुली कलिता मेधी:

डॉ. प्रशांत यादवराव पडोलेः

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पीएम ई-ड्राइव के अंतर्गत सार्वजनिक परिवहन के दीर्घकालिक उत्सर्जन संबंधी प्रभाव को मापने के लिए सरकार की क्या योजना है;

(ख) भविष्य में पीएम ई-ड्राइव के अंतर्गत इलेक्ट्रिक सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के विस्तार हेतु योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा ई-बस बेड़े के सफल कार्यान्वयन के लिए राज्यों के साथ समन्वय में सुधार हेतु क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों पर और महानगरों में सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए कोई रूपरेखा तैयार की गई है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा)

(**क**) **से** (**ग**)**:** प्रधानमंत्री ई-ड्राइव स्कीम के तहत, शुरुआत में 40 लाख से अधिक आबादी वाले नौ शहरों नामतः मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, सूरत और पुणे में 14,028 ई-बसें चलाने के लिए 4,391 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसका उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन से होने वाले उत्सर्जन को कम करना है।

सीईएसएल द्वारा प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से समुच्चयन मॉडल पर ई-बसों की खरीद की जाती है। ई-बसों के लिए सहायता राज्य/नगरीय परिवहन उपक्रमों (एसटीयू) के

माध्यम से परिचालन व्यय (ओपेक्स)/सकल लागत अनुबंध (जीसीसी) मॉडल पर प्रदान की जाती है। सीईएसएल, पीएम ई-ड्राइव स्कीम के अंतर्गत ई-बसों के संचालन हेतु राज्यों के साथ समन्वय कर रहा है।

भारी उद्योग मंत्रालय और सीईएसएल द्वारा राज्यों के साथ बैठकें आयोजित की गई हैं। शहरों ने ई-बसों के आवंटन के लिए अपना अनुरोध प्रस्तुत किया है।

(**घ**) **एवं** (**ङ**)**:** इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना एक गैर-लाइसेंस प्राप्त गतिविधि है और निजी उद्यमी भी इस गतिविधि में भाग ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त, पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों और महानगरों सहित पूरे भारत में इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (ईवी पीसीएस) स्थापित करने के लिए 2,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

*****